

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2022—वैशाख 2, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जनवरी 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005), मिशन संचालक, जल-जीवन मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, परिवहन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. (2005), सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त एवं आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को केवल सचिव, परिवहन विभाग एवं परिवहन आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए मिशन संचालक, जल-जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

3. श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. (2008), विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री ए. कुलभूषण टोप्पो, भा.प्र.से. (2003), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग केवल आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री श्याम लाल धावड़े, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला-कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, लोक शिक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

6. श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है.

7. श्री धर्मेंश कुमार साहू, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

8. श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. (2011) कलेक्टर, जिला-गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-महासमुंद के पद पर पदस्थ करता है.

9. श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), संचालक, भू-अभिलेख तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, गृह विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

10. सुश्री नम्रता गांधी, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है.

11. सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ करता है.

12. श्री कुलदीप शर्मा, भा.प्र.से. (2014), आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोरिया के पद पर पदस्थ करता है.

13. श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है.

14. श्री विजय दयाराम के., भा.प्र.से. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, सहकारी, शक्कर कारखाना, कबीरधाम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के पद पर पदस्थ करता है.

15. श्रीमती रोक्तिमा यादव, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है.

16. श्री रोहित व्यास, भा.प्र.से. (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुंगेली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 जनवरी 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त, लोक शिक्षण, प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को केवल आयुक्त, लोक शिक्षण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मार्च 2022

क्रमांक/1099/906/2022/11/6.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा (पश्चिम) की 210 मेगावाट इकाई क्र.-2 के बायलर क्र. एम.पी./3555 को दिनांक 25-03-2022 से 30-04-2022 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कि अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराई जावेगी.
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. पवार, अवर सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 मार्च 2022

क्रमांक एफ 1-28/2021/26.—राज्य शासन एतद्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2020 के माध्यम से सहायक संचालक के पद पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित निम्न अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर सहायक संचालक, समाज कल्याण के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100, ग्रेड वेतन 5400/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल 12) में पैरा 2.1 से 2.12 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए, उनके नाम के सम्मुख कॉलम (5) में दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग की चयन सूची का वरियता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	चयन का वर्ग	पदस्थापना स्थल का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्रीमती ऋचा शर्मा डी-18, भाटीया नॉलेज ट्री के नीचे, सेक्टर-5, देवेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001	अनारक्षित	राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र, माना रायपुर (छ.ग.)

2. उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी. इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा.

2.2 (क) 03 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापेण्ड देय होगा :—

प्रथम वर्ष	—	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	—	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष	—	पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परीक्षा अवधि में स्टापेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.

(ख) परीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब यह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा.

2.3 परीक्षा अवधि के दौरान उक्त अधिकारी को छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाए जाने पर, वे छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

2.4 परीक्षाधीन अधिकारी को अपनी परीक्षा अवधि में निर्धारित परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा. उक्त अधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाने अथवा उसे सेवा के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी. परीक्षाधीन अधिकारी की सेवाएं परीक्षा अवधि के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न हो.

2.5 यह नियुक्ति “मेडिकल बोर्ड” से शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है. मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने पर अथवा पुलिस चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विपरीत तथ्य पाए जाने पर, परीक्षाधीन अधिकारी की सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकेंगी.

- 2.6 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ समाज कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 से शासित होंगे.
- 2.7 चयनित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र/दस्तावेज आदि गलत पाये जाने पर, उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी.
- 2.8 परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस आशय का एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना होगा की उसके द्वारा परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, वह परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर व्यय की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते, प्रशिक्षण एवं यात्रा आदि व्यय शामिल होगा, को शासन को वापसी के लिए उत्तरदायी होगा.
- 2.9 चयनित अधिकारी की परस्पर वरिष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी.
- 2.10 उपरोक्त नियुक्ति माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित याचिका क्रमांक 591/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्यक्षीन होगी.
- 2.11 उपरोक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 कार्य दिवस के भीतर पदस्थापना स्थान में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरीशंकर शर्मा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक 893/अ-82/भू-अर्जन/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	रमपुरा प.ह.नं. 13	0.25	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा.	झिपनिया जलाशय योजना के अंतर्गत बरगड़ा फीडर केनाल में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक 894/अ-82/भू-अर्जन/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	बरगड़ा प.ह.नं. 02	0.18	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा.	झिपनिया जलाशय योजना के अंतर्गत बरगड़ा फीडर केनाल से ग्राम बरगड़ा में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक 895/अ-82/भू-अर्जन/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	सोमईखुर्द प.ह.नं. 02	0.29	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा.	झिपनिया जलाशय योजना के अंतर्गत बरगड़ा फीडर केनाल में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक 896/अ-82/भू-अर्जन/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	भेण्डरवानी प.ह.नं. 02	0.14	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा.	झिपनिया जलाशय योजना के अंतर्गत बरगड़ा फीडर केनाल में प्रभावित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 18 फरवरी 2022

क्रमांक 897/अ-82/भू-अर्जन/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	चिल्फी प.ह.नं. 01	1.65	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) साजा.	झिपनिया जलाशय योजना के डुबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदीपान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 मार्च 2022

क्रमांक 15/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बेलगहना

(ग) नगर/ग्राम-छतौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

500/1झ/9	0.012
500/1झ/3	0.077
500/9	0.486
500/1ञ	0.142
500/1छ2	0.283
500/1झ/1	0.065
500/1झ/6	0.028
500/1झ/7	0.032
500/1ग3	0.053
501/1न/3	0.008
501/25	0.081
501/14	0.081
500/1ग/3	0.028
500/1ख	0.028
501/1न/3	0.012
500/1ग/7	0.105
500/1ग5	0.012
500/1घ3	0.020
0500/24	0.008
500/1ङ/2	0.028
500/1ग11	0.016

(1)	(2)
500/1ग9	0.045
500/1घ/4	0.020
500/1ङ/1	0.016
500/1ग10	0.036
500/1घ2	0.041
502/5	0.012
502/4	0.037
502/7	0.020
502/3	0.073
508/3	0.036
176, 177/10	0.016
505/2	0.045
508/2	0.053
465/1, 474	0.061
466/2	0.037
467/1	0.032
467/2	0.004
466/1	0.004
467/4	0.004
469/2	0.020
469/3	0.077
224/1	0.028
208/2	0.073
208/1	0.032
208/4	0.040
209	0.024
210	0.016
211, 212/1	0.024
211/4, 212/4	0.024
225	0.020
214/3	0.004
214/2	0.053
214/1	0.029
247/1	0.012
219	0.077
66, 67, 68/2	0.077
176, 177/1	0.036
176, 177/17	0.045
171	0.134
170	0.045
22/1क/2	0.045
161/6	0.041
161/1	0.004
80/1	0.081
64/1	0.032
80/3	0.024
78	0.069

(1)	(2)
69, 260, 261/1	0.037
69, 260, 261/4	0.037
69, 260, 261/7	0.008
69, 260, 261/2	0.057
66, 67, 68/1	0.211
64/3	0.045
80/6	0.004
161/8	0.016
58, 59, 60, 61, 62/1	0.097
247/5	0.053
247/2	0.036
247/3	0.036
224/2	0.008
208/3	0.012
465/2	0.041
500/1न/2	0.101
योग	4.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छत्तीसगढ़ जलाशय योजना डुबान एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सारांश मिस्टर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2022

क्रमांक/1341/वा./भू.अ./प्र.क्र./01/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-पखांजूर
(ग) नगर/ग्राम-मौसमटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
149	0.01
151	0.04
योग	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पी.व्ही. 102 से पानावार मार्ग लं. 7.00 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2022

क्रमांक/1342/वा./भू.अ./प्र.क्र./22/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-पखांजूर
(ग) नगर/ग्राम-हरिहरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.078 हेक्टेयर

खसरा नम्बर रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
267	0.01

(1)	(2)
266/2	0.01
266/1	0.01
231	0.012
264/2	0.007
216	0.024
158/1	0.005
योग	0.078

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पी.व्ही. 32 से पी.व्ही 29 मार्ग लं. 5.00 कि. चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2022

क्रमांक/1345/वा./भू.अ./प्र.क्र./26/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-पखांजूर
- (ग) नगर/ग्राम-माटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.637 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/1	0.13
82/1	0.146
82/3	0.003
94	0.012
152/2	0.018

(1)	(2)
155	0.003
158/1	0.087
156	0.104
259/2	0.005
81	0.102
82/2	0.008
153	0.019
योग	0.637

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माटोली पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2022

क्रमांक/1346/वा./भू.अ./प्र.क्र./21/अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-पखांजूर
- (ग) नगर/ग्राम-चांदीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.365 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176	0.012
149	0.024
180	0.088
181/1	0.084
189/3	0.02

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पी.व्ही. 32 से पी.व्ही. 29 मार्ग लं. 5.00 कि. चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य हेतु.
188	0.068	
171/1	0.029	
171/3	0.004	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.
254/2	0.018	
259/3	0.018	
योग	10	0.365
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2022

शुद्धि पत्र

प्रारूप-पांच
(नियम 11 देखिये)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप

क्रमांक/1677/नगानि/2021.—इस विभाग द्वारा पुरा विशेष क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग प्रकाशन संबंधी अधिसूचना क्रमांक/12101/न.ग्रा.नि./2021 दिनांक 04-10-2021 जो छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 10-12-2021 भाग-1, पृ.क्र. 1190 में प्रकाशन हुई है, में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि पुरा विशेष क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-15 की उप-धारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 01 जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये. समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.

यतः उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (3) के अधीन एतद्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (4) के अनुसरण में “छत्तीसगढ़ राजपत्र” में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :—

निरीक्षण स्थल :—

1. संभाग आयुक्त, कार्यालय रायपुर (छ.ग.)
2. कार्यालय कलेक्टर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
3. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, आर.डी.ए. बिल्डिंग, शास्त्री चौक, रायपुर, (छ.ग.)

CORRIGENDUM

FORM-V
(See rule 11)

Form for final publication of existing land use map

No./1677/T&CP/2021.—This is to inform you that Partial Modification is done on Existing Land use map of Pura Special Area letter no. 12101/Tn&p/2021 Dated 04-10-2021 which was Published in Chhattisgarh Gazette dated 10-12-2021, part-1, pageno 1190. Notice is hereby given that the existing land use maps for Pura Special Area

was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) in the Chhattisgarh Gazette dated 01 January 2021 and objections and suggestions were invited from the public under the provision of sub-section (2) of the said section. After giving reasonable opportunity of hearing to all such persons who have filed the objection or suggestion, modifications as considered desirable, are made therein.

Now the existing land use maps for the above planning area is hereby adopted under sub-section (3) of Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps has been duly prepared and adopted. The said adopted maps shall be available for inspection during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette in the following offices of :

Place of Inspection :—

1. Office of the Divisional Commissioner, Raipur, District Raipur (C.G.)
2. Office of the Collector, Raipur, District-Raipur (C.G.)
3. Joint Director Town and Country Planning, RDA Building Shastri Chowk, Raipur (C.G.)

संदीप बांगड़े,
अपर संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th March 2022

No. 16/L.G./2022/II-3-14/2008.—Shri K. L. Charyani, the then Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 10-01-2022 to 14-01-2022 and earned leave for 04 days from 08-02-2022 to 11-02-2022 along with permission to leave headquarters from the evening of 07-02-2022 till the morning of 14-02-2022.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Charyani, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)